66 गिरफ्तारियों में 45 गैर-श्रमिक

आगजनी-भड़काने में बाहरी तत्वों की भूमिका

साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है

लखनऊ/नोएडा, 16 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालिया श्रमिक आंदोलन के दौरान फैली हिंसा और अराजकता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं.

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह महज श्रमिक असंतोष का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें बाहरी तत्वों की सक्रिय भूमिका रही. सूत्रों के अनुसार, अब तक हुई 66 गिरफ्तारियों में से 45 लोग ऐसे पाए गए हैं, जो वास्तविक श्रमिक नहीं हैं.आगजनी की घटनाओं में चिन्हित 17 लोगों में से 11 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 गैर-श्रमिक हैं.वहीं, भड़काने के आरोप में चिन्हित 32 में से 19 को हिरासत में लिया गया है.इसके अतिरिक्त 34 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है, जो श्रमिक न होते हुए भी प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे.जांच एजेंसियों के मुताबिक, साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके कुछ संगठित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.

> मामले में कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स और बाहरी राज्यों से आए लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.सूत्रों का दावा है कि नोएडा के औद्योगिक ढांचे को प्रभावित करने के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई गई थी.हिंसा के दौरान आगजनी, पथराव और उकसावे की घटनाओं में शामिल कई लोग स्थानीय श्रमिक नहीं थे, बल्कि बाहर से आए तत्व थे, जिनका उद्देश्य औद्योगिक माहौल को अस्थिर करना था.स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 12 मई को

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव 12 मई को कराये जाने की गुरुवार को घोषणा की।इन सीटों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है।आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 30 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 मई को की जाएगी और नाम 4 मई तक वापस लिए जा सकेंगे।आवश्यकता पड़ने पर मतदान 12 मई को सुबह 9-00 बजे से शाम 4-00 तक कराया जाएगा। मतों की गिनती मतदान के बाद उसी दिन कराई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 13 मई से पहले संपन्न कर ली जाएगी.

होर्मुज को खोलना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मांग

बीजिंग, 16 अप्रैल. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सर्वसम्मत मांग है.

वांग ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक ओर जहां ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और एक तटीय राज्य के रूप में उसके वैध अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इस जलडमरूमध्य से नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा की गारंटी भी दी जानी चाहिए श्री वांग ने कहा, इस जलडमरूमध्य से सामान्य आवागमन फिर से बहाल करने के प्रयास अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से एक सर्वसम्मत आह्वान का प्रतिनिधित्व करते हैं.श्री वांग ने कहा कि वर्तमान स्थिति युद्ध और शांति के बीच एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि कूटनीतिक समाधान के लिए अवसर का एक दरवाजा भी खुल रहा है.ईरानी सरकार ने होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए एक %विशेष व्यवस्था परिभाषित करने का आह्वान करते हुए यह तर्क दिया कि यह जलमार्ग तेहरान के लिए एक %विशेष संपत्ति% है.गौरतलब है कि यह जानकारी राज्य समाचार एजेंसी आईआरएनए ने दी.

नाकेबंदी के कारण होर्मुज के रास्ते बाधित : चीन

सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने रूस की आरआईए नोवोस्ती को बताया, उन सभी संपत्तियों की तरह जो अन्य देशों के साथ बातचीत के प्रकार और उसके नियमन के लिए एक साधन के रूप में काम करती हैं, उसी तरह से इस जलमार्ग के लिए भी एक विशेष व्यवस्था परिभाषित की जानी चाहिए। इस सप्ताह के अंत में पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान वार्ता विफल होने के बाद वाशिंगटन द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाए जाने के कारण होर्मुज के रास्ते होने वाला नौवहन बाधित है। होर्मुज जलडमरूमध्य सामान्यत: वैश्विक समुद्री तेल प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा संभालता है लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध से उत्पन्न नवीनतम ऊर्जा संकट के केंद्र में वह बना हुआ है.

साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़

बैंक कर्मचारी सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली 16 अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत एक बड़े साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक बैंक कर्मचारी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

यह रैकेट म्यूल बैंक खातों के जरिए संचालित होता था.म्यूल खाते, ऐसे खाते होते हैं जिन्हें अपराधी फर्जी ढंग से खुलवाते हैं और ठगी की रकम उसमें रखते हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया, जिसमें एक पीड़ित के खाते से 10,000 रुपये निकाले गए थे.जांच के दौरान मयूर विहार स्थित एक निजी बैंक शाखा में एक संदिग्ध म्यूल खाते की पहचान हुई.यह खाता साइबर धोखाधड़ी की कई अन्य शिकायतों से भी जुड़ा पाया गया.पुलिस टीम ने केवाईसी दस्तावेजों और लेनदेन के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद सबसे पहले खाताधारक शौकीन को पकड़ा.पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने अपने भतीजे शाहरुख उर्फ जोजो के कहने पर यह खाता खोला था.इसके बाद शाहरूख को गिरफ्तार किया गया, जिसने बैंक कर्मचारी की संलिप्तता का खुलासा किया.

मीट एंड अवॉर्ड समारोह के आयोजकों से धामी ने की भेंट

आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई

देहरादून, 16 अप्रैल. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को उनके आवास में इंडिया डिजिटल इंपॉवरमेंट मीट एंड अवॉर्ड समारोह के आयोजकों ने शिष्टाचार भेंट की और आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.

धामी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन वर्तमान समय की आवश्यकता हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े विविध विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा.उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कांफ्रेंस से प्राप्त निष्कर्ष और सुझाव भविष्य में सकारात्मक परिणाम देने के साथ-साथ राज्य और देश के डिजिटल विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे.उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है.

> राज्य में प्रतिवर्ष छह करोड़ से अधिक श्रद्धालु एवं पर्यटक विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के कारण अनेक आकर्षक डेस्टिनेशन उपलब्ध हैं.राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण है, जिससे फिल्म उद्योग के क्षेत्र में व्यापक बदलाव संभावनाएं मौजूद हैं.इसके अतिरिक्त औद्योगिक निवेश के लिए भी राज्य में बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, जिन्हें और विकसित करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं.

बंगलादेश में खसरे का प्रकोप तेज, 24 घंटे में आठ बच्चों की मौत

ढाका. बंगलादेश में खसरा (मीजल्स) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में आठ बच्चों की मौत हो गई है।यह जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने दी है।इस दौरान देश भर के अस्पतालों में खसरा जैसे लक्षणों वाले 1,191 से अधिक मरीज भर्ती किए गए, जिनमें से 92 मामलों की प्रयोगशाला जांच में खसरे की पुष्टि हुई है।इन आठ मौतों के साथ मृतकों की संख्या और बढ़ गई है। अब तक कम से कम 34 बच्चों की मौत की पुष्टि खसरा संक्रमण से हो चुकी है, जबकि 172 बच्चों की मौत खसरे जैसे लक्षणों के कारण हुई है.

अनिल अंबानी को सुको से राहत नहीं

नई दिल्ली, 16 अप्रैल.उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी.

यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने टिप्पणी की कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश उस मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिसका फैसला होना बाकी है और उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया.

हरिवंश को उप सभापति चुना जाना तय

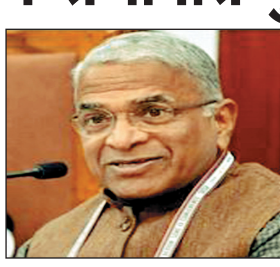

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हरिवंश का उच्च सदन के उप सभापति के पद पर निर्विरोध चुना जाना तय है क्योंकि इस चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और विपक्ष की ओर से किसी ने नामांकन नहीं किया है.

हरिवंश ने उच्च सदन के उप सभापति के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन किया है और उनके नामांकन के समर्थन में पांच प्रस्ताव दिये गये हैं। चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि गुरुवार को दोपहर बारह बजे तक थी।इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार निर्धारित समय तक विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है इसलिए श्री हरिवंश का उपसभापति चुना जाना तय है। इस तरह हरिवंश लगातार दूसरी बार उप सभापति चुने जायेंगे.

> उनका दूसरा कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया था।सूत्रों ने कहा है कि श्री हरिवंश के समर्थन में प्रस्ताव सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने दिये हैं। श्री नड्डा के प्रस्ताव का भाजपा सदस्य एस. फांगनोन कोन्याक ने समर्थन किया है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावकों में नितिन नवीन,निर्मला सीतारमण, समर्थनकर्ता सुरेंद्र सिंह नागर, संजय कुमार झा, समर्थनकर्ता उपेंद्र कुशवाहा, और जयंत चौधरी, समर्थनकर्ता मिलिंद मुरली देवड़ा शामिल हैं.

आज का इतिहास

- 1799 – श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू.4 मई को टीपू सुल्तान की मौत के साथ इसका अंत हुआ.
- 1941 – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया.
- 1946 – सीरिया ने फ्रांस से आजादी मिलने की घोषणा की.
- 1947 – श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्म.
- 1971 – मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिल कर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया.

हनी-ट्रैप के जरिए 500 से अधिक महिलाओं से दो करोड़ की ठगी

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक कुख्यात साइबर जालसाज और जबरन वसूली करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर डेटिंग और शादियां तय करवाने वाली वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से अधिक महिलाओं को ठगने और ब्लैकमेल करने का आरोप है.पुलिस के अनुसार, आरोपी आनंद कुमार (35) कई फर्जी पहचानों का इस्तेमाल कर महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाता था.उसने अब तक लगभग दो करोड़ रुपये की वसूली की है और कई मामलों में निजी सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे ऐंठे हैं.दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने वैभव अरोड़ा नाम के व्यक्ति द्वारा करीब सात लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई.आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला का भरोसा जीता और फिर मेडिकल इमरजेंसी एवं वित्तीय संकट का बहाना बनाकर पैसे लिए.जब महिला ने पैसे वापस मांगे, तो उसने संपर्क तोड़ दिया और खुद की मौत की झूठी खबर फैला दी ताकि महिला उसका पीछा छोड़ दे.

भाजपा आई तो माफिया झाड़ू लगाएंगे : योगी

'न दंगा, न कर्फ्यू' : योगी ने गिनाए यूपी के मॉडल, योगी बोले- हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे

चुनावी रण में योगी : बंगाल में कानून-व्यवस्था मुद्दा

कोलकाता/लखनऊ, 16 अप्रैल. पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी आक्रामक शैली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की.

आसनसोल, बीरभूम और बोलपुर में आयोजित जनसभाओं में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कानून-व्यवस्था, माफियाराज और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया.योगी ने जनता से डरने की बजाय खुलकर मतदान करने की अपील की और दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश में माफिया और गुंडाराज खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के 'डबल इंजन सरकार' मॉडल को उदाहरण के तौर पर पेश किया और कहा कि वहां अब न दंगा होता है, न कर्फ्यू लगता है.योगी ने यह भी कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक पहचान की गारंटी दे सकती है.उनके इस बयान ने बंगाल की सियासत को और गर्म कर दिया है, जहां पहले से ही भाजपा और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

तमिलनाडु, बंगाल में वीएम-वीवीपैट मशीनों का संचालन शुरू

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने गुरुवार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाइयों का संचालन शुरू कर दिया जहां 23 को विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान होना है.यह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तैयारियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.तमिलनाडु और बंगाल में 23 को होने वाले प्रथम चरण के चुनावों के लिए वीएम-वीवीपैट प्रणाली का संचालन शुरू हो गया है.

सफल अपील पर चुनाव आयोग जारी करे पूरक सूची : सुको

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया और मताधिकार के सवाल पर स्पष्टता ला दी है. अदालत ने साफ कहा कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता. यह फैसला उन याचिकाओं पर आया, जिनमें मतदाता सूची से हटाए गए लोगों ने अंतरिम राहत के रूप में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण मतदान से पहले अपीलों का निपटारा कर देते हैं, तो सफल आवेदकों को पूरक मतदाता सूची में शामिल किया जाए। इससे ऐसे लोगों के लिए मतदान का रास्ता खुला रहेगा, जिनकी अपील समय पर स्वीकार हो जाती है। यह फैसला चुनावी पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. यह मामला 'विशेष गहन संशोधन' प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसके तहत मतदाता सूची की व्यापक जांच की गई थी.

> **ममता बनर्जी बोलीं- धैर्य का मिला फल, न्याय हुआ**
>
> **कोलकाता.** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका पर गर्व जताया है. उन्होंने पहले ही लोगों से धैर्य रखने की अपील की थी और अब अदालत के आदेश से यह साफ हो गया है कि जिन लोगों ने अपील की है, उन्हें न्याय मिलेगा।ममता बनर्जी ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक फैसले सुनाएंगे और उसके बाद सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे पात्र लोगों को मतदान का अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र और न्याय की जीत करार दिया.

अगले 48 घंटे भारी : देश में हीटवेव का रेड अलर्ट

- **दिल्ली-यूपी में लू का कहर, पारा पहुंचेगा 45 डिग्री**
- **उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर**

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. देशभर में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले 48 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकते हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी इलाकों में भीषण हीटवेव चलने वाली है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में लू का असर तेजी से बढ़ेगा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत में मौसम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा, जहां तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का अनुमान है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि साफ आसमान और बारिश की कमी के कारण जमीन तेजी से गर्म हो रही है, जिससे हीटवेव की स्थिति और गंभीर हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में हुई बारिश के बाद अब आसमान साफ हो गया है, जिससे सूरज की तेज किरणें सीधे धरती को गर्म कर रही हैं। यही कारण है कि हीटवेव की स्थिति तेजी से बन रही है.

नितिन नवीन समेत 16 सदस्यों ने राज्यसभा में ली शपथ

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. राज्यसभा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत 16 नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली.

संसद के मौजूदा बजट सत्र में तीन दिन की विशेष बैठक के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी।शपथ लेने वालों में असम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सदस्य तेराश गोवाला, जोगेन मोहन और प्रमोद बोरा शामिल हैं।बिहार से भाजपा के नितिन नवीन और शिवेश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राम नाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने सदस्यता की शपथ ली।छत्तीसगढ़ से भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेतम ने शपथ ग्रहण किया।हरियाणा से कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और भाजपा के संजय भाटिया को शपथ दिलाई गयी. हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के अनुराग शर्मा, महाराष्ट्र से भाजपा के विनोद तावड़े और ओडिशा से भाजपा के सुजीत कुमार ने सदन की सदस्यता ग्रहण की.

देशभर में | **238 एलपीजी वितरकों पर दंड लगाया और अनियमितताओं के कारण 63 को निलंबित किया**

एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ 2500 छापे

नई दिल्ली ,16 अप्रैल.मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बीच रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एलपीजी की जमाखोरी और काला बाज़ारी के खिलाफ तेजी तथा मजबूती के साथ अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार को देश भर में 2500 से अधिक छापे मारे गये.

पश्चिम एशिया संकट के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि खान मंत्रालय कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं से निपटने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को देशभर में 2,500 से अधिक छापे मारे गए, जबकि तेल विपणन कंपनियों ने 238 एलपीजी वितरकों पर दंड लगाया और अनियमितताओं के कारण 63 को निलंबित किया.

खान मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय ने हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत की है और अप्रैल के प्रारंभ में एल्युमिनियम उत्पादकों, तांबा उद्योग प्रतिनिधियों और प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे एफआईएमआई, फिक्की, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई और एसोचैम के साथ तीन महत्वपूर्ण बैठकें कीं.इन बैठकों से प्राप्त सुझावों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है.सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि धातु सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एलपीजी आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जोर दिया कि होरमुज़ जलडमरूमध्य से संबंधित घटनाक्रमों के बावजूद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.

नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने, आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा रखने, ऊर्जा की बचत करने और पीएनजी तथा विद्युत आधारित खाना पकाने जैसे वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की सलाह दी गई है.

> **विजय का घोषणापत्र : महिलाओं-किसानों के लिए तोहफे**
>
> **चेन्नई.** तमिलनाडु की राजनीति में नई एंट्री करने वाले अभिनेता-से-राजनेता विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम का चुनावी घोषणापत्र जारी कर सियासी हलचल तेज कर दी है। 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी इस घोषणापत्र में महिलाओं, किसानों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में रखते हुए कई बड़े और आकर्षक वादे किए गए हैं।विजय ने खासतौर पर महिलाओं को साधने के लिए हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता और साल में छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, जो सीधे तौर पर परिवारों के खर्च को कम करने का प्रयास माना जा रहा है। इसके अलावा, किसानों के लिए कर्ज माफी और बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे ऐलान भी किए गए हैं।तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय ने अपने चुनावी घोषणापत्र के जरिए राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

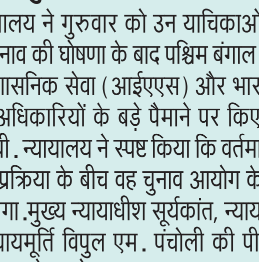

> **अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज**
>
> **नयी दिल्ली.** उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच वह चुनाव आयोग के इन फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि चुनावों के दौरान ऐसे तबादले सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और यह कई राज्यों में होते हैं.चुनाव आयोग के राष्ट्रव्यापी आंकड़ों की जांच करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि आंकड़ों से पता चला कि अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए गए अधिकारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित अधिकारियों की संख्या से कहीं अधिक थी.